प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

15.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00 बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत आज अपने सरकारी आवास ओकओवर से 18 ई–टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैक्सियां शिमला जिले के चार, कांगड़ा व किन्नौर के तीन–तीन, चम्बा–कुल्लू व सोलन के दो–दो और हमीरपुर व सिरमौर जिले के एक–एक युवाओं को प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने कार मालिकों को ई–टैक्सी की चाबी सौंपी और उन्हें रोजगार के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है और इस पर एक करोड़ 28 लाख रूपए की सब्सिडी खर्च की है।

साथ दी गई, इस योजना के तहत अगर एक गाड़ी 14 लाख की है तो उसमें □7 लाख सरकार देगी, जो गाड़ी खरीदने वाला युवा साथी है उसको सिर्फ मार्जिनल मनी का 10 प्रतिशत देना पड़ेगा यानी कि 14 लाख में से1 लाख 40 हजार रूपये देना पड़ेगा और उन्हें बैंक गारंटी भी कोई देनी नहीं पड़ेगी सरकार के द्वारा युवाओं को यह आश्वासन दिया गया है कि हर एक गाड़ी का हर महीने आपको जो किराया वो मिलेगा और किराया गाड़ी के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है यानी कि 10 से 14 लाख की गाड़ी को 50000, 15 से 20 लाख की गाड़ी को 65000 और 20 लाख से ऊपर की गाड़ी को 75 हजार और इसके अलावा उन्हें ये भी अश्वासन है कि सरकार आपकी गाड़ी 4 साल लगाएगी और उसके बाद आप गाड़ी को ठीक रखोगे तो 3 साल और लगाएगी 4 और 3 7–7 तो 80 जगह सरकारी क्षेत्र में यह गाड़ियां लग चुकी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष मॉनसून के दौरान आई आपदा के कारण पथ परिवहन निगम को नुकसान हुआ है और सरकार इसकी भरपाई की कोशिश कर रही है।

डीए घोषणा

प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर 3 प्रतिशत डीए का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों के महासम्मेलन में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस वर्ष एक अप्रैल से सितम्बर तक के एरियर की राशि भी दीपावली से पहले मिल जाएगी जबकि अक्तूबर के वेतन के साथ नवम्बर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिलनी शुरू हो जाएगी।

राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में सौ प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी चार हज़ार रुपये से दोगुना करके आठ हज़ार रुपये प्रति माह कर दिया गया

है। इससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर–पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, को आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि दो आश्रित बच्चों तक के लिए शिक्षा अनुदान को एक हज़ार रुपये से बढ़ाकर दो हज़ार रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। विवाह अनुदान भी प्रति लाभार्थी 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित दरें इस वर्ष पहली नवंबर से प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 2 सौ 57 करोड़ रुपये होगा।

कार्यशाला

भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी शिमला द्वारा आज जनजातीय जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि पीआईबी केन्द्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है। इस अवसर पर पीआईबी के मीडिया अधिकारी अहमद खान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व मीडिया कर्मी मौजूद रहे।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7 बजकर 45 मिनट पर। नमस्कार।